



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2024

भाद्रपद 21, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या 1740114 / 12-2099 / 156-2023-834-2024

लखनऊ, 12 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

प०आ०-238

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित कीटनाशकों का विक्रय, वितरण और प्रयोग बासमती चावल उत्पादकों के हित में नहीं है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं :-

(एक) नीचे अनुसूची में दिए गए कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग के कारण चावल के दानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशेष स्तर (एम०आर०एल०) से अधिक कीटनाशक अवशेषों का जोखिम है;

(दो) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ ने उत्तर प्रदेश राज्य में, बासमती चावल में कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए कृषि रक्षा रसायनों के विकल्प के रूप में एकीकृत रोग प्रबन्धन (आई०डी०एम०) मॉड्यूल की संस्तुति की है;

(तीन) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (पौध संरक्षण प्रभाग), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एफ०सं० 13035/46/2016-पीपी-1 (वॉल्यूम-II) पार्ट-1 (ई 79858), दिनांक 23 जून, 2021 द्वारा 'कीटनाशकों विशेषकर ट्राइसाइक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन के सुरक्षित और न्यायोचित प्रयोग' हेतु एस०ओ०पी० (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी किया है, जिसमें वैकल्पिक कीटनाशकों के प्रयोग की संस्तुति की गयी है;

(चार) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारत सरकार ने भी सूचित किया है कि यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी देश जैसे आयातक देशों में कीटनाशकों के अधिकतम अवशेष स्तर के कड़े मानकों के कारण बासमती चावल के निर्यात को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में बासमती चावल के निर्यात में 15% की गिरावट आई है। एपीडा ने उत्तर प्रदेश की विरासत बासमती उपज को बचाने और अन्य देशों को बासमती चावल के बाधा मुक्त निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए इन कीटनाशकों पर पाबंदी/निर्बंधन लगाने का अनुरोध किया है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त कीटनाशक बासमती चावल के निर्यात और खपत में संभावित बाधा हैं;

और, चूँकि, पूर्वोक्त कीटनाशकों के विकल्प जिनका अवशेष प्रभाव कम है, बाजार में उपलब्ध हैं;

और, चूँकि, उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य के तीस बासमती उत्पादक जिलों में बासमती धान की फसल पर, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित कीटनाशकों के विक्रय, वितरण एवं प्रयोग पर प्रतिषेध लगाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि ये कीटनाशक बासमती चावल के निर्यात और खपत में संभावित बाधा हैं;

अतएव, अब, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1968) की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के तीस जिलों यथा आगरा, अलीगढ़, औरैया, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड, हाथरस, मथुरा, मेनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर और सम्भल में, बासमती चावल में, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित कीटनाशकों के सभी प्रकार के फार्मूलेशन की बिक्री, वितरण और प्रयोग को प्रतिषिद्ध करती हैं, ताकि गुणवत्तायुक्त बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि की जा सके।

अनुसूची में उल्लिखित समस्त प्रविष्टियों की शुद्धता कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रम संख्या	कीटनाशक का नाम
1	ट्राइसाइक्लाज़ोल
2	बुप्रोफेज़िन
3	एसीफेट
4	क्लोरपाइरीफॉस
5	हेक्साकोनोजोल
6	प्रोपिकोनाज़ोल
7	थायोमैथाकसाम
8	प्रोफेनेफॉस
9	इमिडाक्लोप्रिड
10	कार्बेण्डाजिम

आज्ञा से,  
रविन्द्र,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1740114/XII-2099/156/2023-834-2024, dated September 12, 2024 :

No. 1740114/XII-2099/156/2023-834-2024

*Dated Lucknow, September 12, 2024*

WHEREAS the State Government is of the opinion that the sale, distribution and use of pesticides indicated in the Schedule below are not in the interest of Basmati rice growers, in view of the following reasons namely :—

(i) There is a risk of higher pesticide residues than the Maximum Residue Level (MRL) fixed by the Competent Authority in rice grains on account of use of the agro-chemicals given in the Schedule below;

(ii) The Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut recommended Integrated Disease Management (IDM) module as an alternative to agrochemicals to control pests and diseases of Basmati rice in the State of Uttar Pradesh;

(iii) The Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare (Plant Protection Division), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India has issued SOP (Standard Operating Procedure) for 'Safe and Judicious Use of Pesticides Specific to Tricyclazole and Buprofezin' vide F.No. 13035/46/2016-PP-1 (Vol.-II) Part-I (e 79858), dated June 23, 2021 wherein it has recommended alternative pesticides;

(iv) The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Government of India has also informed that export of Basmati rice is facing challenges due to the stringent norms of Maximum Residue Level of Pesticides in importing countries like European Union, United States of America and Gulf countries. The export of Basmati rice has declined by 15% during 2021-22 as compared to 2020-21. The APEDA requested for ban/restriction of these pesticides to save the heritage Basmati produce of Uttar Pradesh and to ensure hassle free export of Basmati rice to other countries;

AND, WHEREAS, the aforesaid pesticides are a potential constraint in export and consumption of Basmati rice;

AND, WHEREAS, the alternative to the aforesaid insecticides, which have low residue effects, are available in the market;

AND, WHEREAS, in view of the above, it has become imperative to prohibit the sale, distribution and use of pesticides indicated in the Schedule below on Basmati rice crop in thirty Basmati growing district of the State of Uttar Pradesh for the reason of them being a potential constraint in export and consumption of Basmati rice;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (Act no. 46 of 1968) and all other powers enabling in this behalf, the Governor is pleased to prohibit the sale, distribution and use of all types of formulations of pesticides detailed in the Schedule below in Basmati rice crop in thirty districts of the State of Uttar Pradesh *i.e.*- Agra, Aligarh, Auraiya, Baghpat, Bareilly, Bijnor, Badaun, Bulandshahar, Etah, Kasganj, Farrukhabad, Firozabad, Etawah, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Hapur, Hathras, Mathura, Mainpuri, Meerut, Moradabad, Amroha, Kannauj, Muzaffarnagar, Shamli, Pilibhit, Rampur, Saharanpur, Shahjahanpur and Sambhal for a period of sixty days from the date of publication of this notification in the *Gazette*, so that the quality Basmati rice export may be enhanced.

## SCHEDULE

Sl. no.	Name of pesticide
1	Tricyclazole
2	Buprofezin
3	Acephate
4	Chlorpyrifos
5	Hexaconazole
6	Propiconazole
7	Thaimethoxam
8	Profenofos
9	Imidacloprid
10	Carbendazim

By order,  
RAVINDER,  
*Pramukh Sachiv.*